अंक-9, दिसंबर 2025

पर्यावरण संवाद

प्रकृति एवं देशज संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए

जस्ट ट्रांजिशन से जस्ट ट्रांसफॉरमेशन की ओर!

वृक्ष नहीं हैं स्त्रियां

आप उखाड़ कर
नहीं ले जा सकते
कहीं और नहीं लगा सकते
कोई एक बड़ा वृक्ष
जिसकी जड़ें गहरी हों
प्रकृति आपका साथ नहीं देगी
धूप, पानी और मिट्टी भी
आपके प्रयासों को
फिर से हरा नहीं कर पाएंगे
पर स्त्रियां वह घना वृक्ष हैं
जो जड़ समेत उखाड़ देने के बावजूद
कहीं पर भी लग जाती हैं
हर कहीं हरी हो जाती हैं
भूगोल के किसी भी अनजान
हिस्से और परिवेश में

उसकी जड़ें अतीत का
आग्रह नहीं करतीं
वर्तमान और भविष्य तक
फिर से फैल जाती हैं स्त्रियां
आने वाली अनंत पीढ़ियों तक

बावजूद इसके
वृक्ष नहीं हैं स्त्रियां
वे चुनौती नहीं देतीं प्रकृति को
न ही प्रकृति से खुद को
बड़ा मानती हैं
बार बार झुकती हैं स्त्रियां
वृक्षों के आगे
क्योंकि स्त्रियां प्रकृति का सम्मान हैं...

– **अश्विनी कुमार पंकज**

संपादक
घनश्याम

संपादक मंडल
उदय
अबरार ताबिन्दा
पूनम रंजन
सीमांत सुधाकर
महेश मिश्रा
तहा सैफुद्दीन
सालगे मार्डी
कोर्दुला कुजुर
ऐनी टुडू
श्रावणी
शशि बारला

संवाद सूत्र
मालती कुमारी
आनंद मरांडी
कुंदन कुमार भगत
सीमा
सुशीला हेम्ब्रम
मिनीला बास्की

कला संपादक
शेखर

साज-सज्जा
जमील, राकेश व जावेद

संपादन कार्यालय
पर्यावरण कक्ष "संवाद" 52 बीघा,
मधुपुर, झारखंड
की ओर से प्रकाशित
मुख्य कार्यालय
'संवाद', 104/A उर्मिला इन्क्लेव,
पीस रोड, राँची - 834001
www.samvad.net

घनश्याम द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तथा
आई.डी.पब्लिशिंग, राँची द्वारा मुद्रित
सीमित प्रसार

विचार
- जस्ट ट्रान्जिशन क्या है? – **कृष्ण कान्त** 5
- जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण जीवन – **पूर्णिमा बिरुली** 7

प्रगति-पथ
- कोयले के दम पर प्रगति करेगा संताल परगना – **पर्यावरण संवाद डेस्क** 8

चिंतन
- जस्ट ट्रांजिशन से जस्ट ट्रांसफॉरमेशन की ओर – **घनश्याम** 9

उत्क्रमित विकास
- झारखण्ड का बदलता जलवायु – **डॉ. नितीश प्रियदर्शी** 11
- जलवायु परिवर्तन : गाँव की तबाही का कारण – **निरसो हांसदा** 12

खाद्य मेला
- सुन्दरपहाड़ी में आयोजित वन्य खाद्य मेला – **कृष्ण कान्त** 13

अनुभव
- जलवायु संकट का मेरा अनुभव – **सालगे मार्डी** 15

यात्रा
- जस्ट ट्रांजिशन यात्रा : जलवायु संकट से निजात पाने की एक पहल – **गुलाब चंद्र** 16

रिपोर्ट
- जलवायु संकट का महिलाओं पर प्रभाव – **पर्यावरण संवाद डेस्क** 20

खेती-किसानी
- खेती-किसानी महज व्यवसाय नहीं, बल्कि सामुदायिक संस्कृति – **पर्यावरण संवाद डेस्क** 22

कलम-कैमरा-कूची
- जस्ट ट्रांजिशन : वैश्विक विमर्श, जलवायु संकट और कलाकार की संवेदनात्मक पहल – **शेखर** 23

जस्ट ट्रांजिशन से जस्ट ट्रांसफॉरमेशन की ओर!

आज *जब दुनिया में कथित विकासवाद का मकड़ा अपने बिछाए जाल में खुद फंसता जा रहा है, तब एक नया सूत्र वाक्य उछला जा रहा है... "जस्ट ट्रांजिशन" का! यह इसलिए उछाला गया है ताकि जलवायु संकट और नैसर्गिक असंतुलन की समस्याओं से निजात पाने का भ्रम पैदा किया जा सके। उक्त संकट से उबरने के लिए किए जा रहे बुनियादी संघर्ष की धार को कुंद किया जा सके। यह आसन्न संकट बढ़ रही विषमता से लड़ने का निर्णायक रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? आइए, जरा इसे थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करें। (इस अंक के कुछ आलेख इसकी गंभीरता को तलाशने की एक कोशिश है)।*

दुनिया के अधिकांश विकसित देश आज जिसे "जस्ट ट्रांजिशन" कह रहे हैं उसमें छलावा ज्यादा है, वास्तविकता कम! सन् 1970 के शुरू हुआ यह सूत्र वाक्य अभी कपोल कल्पना जैसा ही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ब्राजील का कोप-30 का वैश्विक सम्मेलन जो 10 से 21 नवम्बर 2025 को सम्पन्न हुआ, जिसमें जस्ट ट्रांजिशन पर आम सहमति नहीं बन पाई। इसमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने का कोई बाध्यकारी (बाइंडिंग) समझौता नहीं हो पाया। इससे यह साबित होता है कथित विकसित देश दिखाने को तो जस्ट ट्रांजिशन की बात कह रहे हैं, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के कारगर तरीके को अंगीकार करने से कतरा रहे हैं। लेकिन दुनिया के गरीब और विकासशील मुल्कों का दबाव इतना जबरदस्त है कि महिलाओं, देशज लोगों और अफ्रीकी देशों के समुदायों के अधिकारों को उक्त सम्मेलन में मान्यता देनी पड़ी।

जलवायु संकट से निजात पाने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं – पहला मीटिगेशन और दूसरा एडेपटेशन। दोनों तरीके तबतक कारगर नहीं हो सकते जबतक "समता और न्याय मूलक" विचारों की प्रतिबद्धता के साथ इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जाता। इसलिए जस्ट ट्रांजिशन एक प्रारंभिक अवस्था है। एक संक्रमणकलीन दौर का तात्कालिक समाधान है। दीर्घकालिक और न्यायमूलक समाधान तो जस्ट ट्रांसफॉरमेशन ही है। इसलिए आइए, जस्ट ट्रांजिशन को तर्कसंगत ढंग से अमलीजामा पहनाते हुए "जस्ट ट्रांसफॉरमेशन तक की सतत और दीर्घकालिक यात्रा" की ठोस एवं नैतिक शुरुआत करें।

जस्ट ट्रान्जिशन क्या है?

– कृष्ण कान्त

मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक व पारिस्थितिकीय परिवेश में परिवर्तन अपरिहार्य है। अक्सर इन परिवर्तनों से सबसे अधिक प्रभावित वंचित समुदाय ही होते हैं जिनकी निर्भरता अपने स्थानीय संसाधनों पर सबसे अधिक रहती है और नीतिगत निर्णयों में उनकी भागीदारी या हितों का समावेशन नहीं होने से इन परिवर्तनों का सबसे अधिक दंश उन्हें ही झेलना पड़ता है। इतिहास साक्षी रहा है कि जब कभी भी आकस्मिक बदलाव की स्थिति आई है श्रमिक और वंचित समाज पर इसका बोझ सबसे अधिक पड़ा है। इस तरह के निरन्तर बदलाव से सीख लेते हुए समाज और सरकारों को न्याससंगत संक्रमण या जस्ट ट्रान्जिशन की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत आज सबसे ज्यादा होती जा रही है।

जस्ट ट्रान्जिशन यानी न्यायोचित परिवर्तन की अवधारणा उदारीकरण के दौर से पहले ही 70 के दशक में चलन में आई जहां अमेरिका में ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने इसकी मांग की थी। इसका उद्देश्य तात्कालिक तौर पर जल और वायु प्रदूषण से संबंधित नये नियमों से प्रभावित तेल, रसायन और परमाणु क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये उनकी आजीविका के साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर समाधान निकालना था। शुरुआती दौर में इस परिवर्तन को लेकर धारणा थी कि यह पर्यावरण संरक्षण के कारण अपनी रोजी रोटी गंवाने वाले मजदूरों के हकों की हिफाजत के लिये श्रमिक संगठनों के प्रयास हैं परन्तु धीरे धीरे इस परिवर्तन को लेकर सोच व्यापक होती गई और इसमें जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न परिस्थितियों से सामना करने के लिये विभिन्न हितभागियों के समावेशी मॉडल और न्यायसंगत निवेश पर सहमति बनती गई जिसमें स्थानीय रोजगार, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संकट का समाधान शामिल हैं। इसके साथ ही मजदूर संगठन जस्ट ट्रान्जिशन को जलवायु परिवर्तन पर हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल करने की मांग करने लगे।

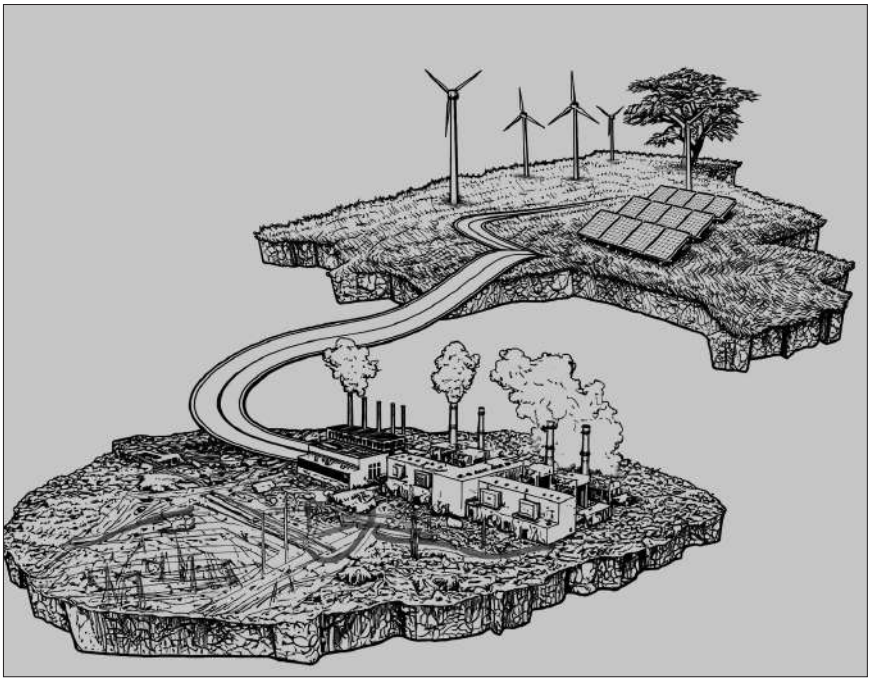

एक न्यायोचित परिवर्तन या जस्ट ट्रान्जिशन समतामूलक और समावेशी होना चाहिये जो यह सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन के लाभ और चुनौतियां समाज में समान रूप से साझा हों और इस परिवर्तन को लाने में जो लोग इससे प्रभावित हों उन सभी की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हो।

जस्ट ट्रान्जिशन – जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में

पिछले कुछ दशकों से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से लगभग सभी देश प्रभावित हो रहे हैं और यह चिन्ताजनक समय है कि यदि इसके अनुकूलन के लिये उचित उपाय नहीं किये गये तो इनके दूरगामी प्रभाव अपरिवर्तनीय और बहुत ही गंभीर होने वाले हैं जिससे उबर पाना नामुमकिन होगा।

इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कई देशों ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये कवायद शुरू कर दी है और हरित तथा कार्बनमुक्त अर्थव्यवस्था को लेकर नीतियां और नियम बना रहे हैं।

पेरिस समझौता में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिये यह भी निर्णय लिया गया कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर सीमित करने के लिये सभी शामिल देश अपनी कार्यप्रणाली में उपयुक्त बदलाव लायेंगे।

जीवाश्म ईंधन और जलवायु परिवर्तन

जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जलवायु परिवर्तन के बहुत बड़े कारक हैं। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण ह्रास की गति को तेज करता है। ये ईंधन प्राचीन जीवाश्म से बने होते हैं और इनको जला कर उर्जा के लिये उपयोग में लाया जाता है। जलने के क्रम में ये बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाई आक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ते हैं जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न होता है जो कि वैश्विक तापमान बढ़ने के प्रमुख कारकों में से एक है। जलवायु परिवर्तन पर अन्तरसरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 2018 में कुल कार्बनडाई आक्साईड उत्सर्जन का 89 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित हुआ है। इसके अतिरिक्त इनसे होने वाले उत्सर्जन से वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट भी गहराता जा रहा है। लगातार बढ़ते तापमान के प्रभाव से मौसम में आकस्मिक परिवर्तन हो रहे हैं और जैव विविधता भी कम होती जा रही है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। जहां एक ओर आईपीसीसी अगले दशक में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अन्दर रखने की हिदायत दे रही है वहीं वर्तमान आंकड़े दर्शाते हैं कि जीवाश्म ईंधन के उत्पादन की मात्रा 2030 तक वांछित स्तर से दुगुनी हो जायेगी।

जहाँ हाल ही में ब्राजील में हुए कॉप-30 सम्मेलन में वनों की कटाई, महिलाओं और स्थानीय निवासियों के नीतिगत निर्णय में भागदारी, विभिन्न पक्षों के बीच समन्वय और सहयोग तथा तकनीकी हस्तांतरण आदि विषयों पर सहमति बनी है वहीं जीवाश्म ईंधन के उत्पादन व उपयोग पर विभिन्न देशों के रणनीतिक हितों के कारण कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है।

जलवायु परिवर्तन और जस्ट ट्रान्जिशन से जुड़े अन्य मुद्दे

जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जलवायु परिवर्तन में जीवाश्म ईंधन के अतिरिक्त खनन, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का स्वास्थ्य व आजीविका पर दुष्प्रभाव, वनों की कटाई, खेती में रसायन के अत्यधिक प्रयोग से बंजर होती जमीन से भी लोगों के रोजगार, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण व जैव विविधता पर गहरा असर पड़ता है।

इनके रासायनिक प्रभाव से झारखण्ड जैसे कई प्राकृतिक सम्पदा बहुल क्षेत्रों में वन्य और मछली, घोंघे, झींगा आदि की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। गिरिडीह में उसरी नदी के किनारे एक होटल का संचालन कर रहे मुकेश बताते हैं कि स्टील उद्योग के बढ़ते उत्सर्जन के कारण यहाँ का पानी लाल हो रहा है और इसके चलते उनके यहाँ बन रहे चावल की भी गुणवत्ता कम हुई है जिसका बुरा असर उनकी कमाई पर पड़ा है। वहीं आसपास के कई लोग लगातार फर्नेस से उत्सर्जित स्लैग यहां वहां अनियोजित और असुरक्षित ढगं से फेंके जाने के कारण जमीन की उर्वरकता में कमी की भी शिकायत कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में जंगल से वनोपज चुन कर अपनी जीविका चलाने वाले परिवार भी जैव विविधता में आ रही कमी के कारण असहाय महसूस कर रहे हैं और प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क आमदनी अर्जित करने की व्यवस्था से वंचित होते जा रहे हैं। श्वांस संबंधित बीमारियां और गैर संक्रामक बीमारियां जैसे मधुमेह, रक्तचाप, थायराईड, कैंसर आदि के मामले भी अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं। इन बीमारियों का सम्बन्ध जीवनशैली और आहार में परिवर्तन के साथ रसायनों के मानव शरीर पर बढ़ते कुप्रभाव से भी है जिनसे अन्तःस्रावी ग्रन्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

न्यायोचित परिवर्तन में चुनौतियां व संभावनाएं

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे समाज के आजीविका, स्वास्थ्य व पर्यावरण को प्रभावित करता है और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर इसका अधिक या कम असर पड़ता है। इनकी सही संख्या का आकलन नहीं होने के कारण न्यायोचित परिवर्तन की दीर्घकालिक योजना बनाना कठिन है। कई देश जैसे जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका आदि में जहाँ इसके प्रयोग काफी आगे बढ़ चुके हैं वहाँ उससे प्रभावित लोगों की संख्या और हरेक वर्ग से संबंधित विशिष्ट तथा सामान्य समस्याओं का गहन आकलन किया गया था। उदारहण के तौर पर झारखण्ड में कोयला उद्योग के जस्ट ट्रान्जिशन से प्रभावित समूह में मात्र कोल इंडिया के कर्मी ही नहीं आते अपितु तमाम संविदाकर्मी, क्षेत्र में कोयला व्यवसाय से जुड़े सभी छोटे, बड़े उद्योग के संचालक और उनके कर्मी, औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से कोयला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में जुड़े सभी दुकानदार और कुशल तथा अकुशल कर्मी भी आते हैं।

भारत में इस प्रक्रिया की शुरूआत हाल ही में हुई है और झारखण्ड इसमें अग्रणी रहा है जहाँ इसके आकलन और नियोजन के लिये राज्य में एक जस्ट ट्रान्जिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वहीं नागर समुदाय की ओर से टास्क फोर्स तथा अन्य हितधारकों के समक्ष जमीनी आंकड़ों और अनुभवों को रख कर इस प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिये सारथी जस्ट ट्रान्जिशन नेटवर्क भी निरन्तर काम कर

रहा है। जरूरत इस बात की है कि समग्रता से संगठित और असंगठित वर्ग के लोगों की स्थिति का आकलन करते हुए उनके अनुकूलन की योजनायें बनाई जायें।

प्रायः इस क्षेत्र में पूर्व से ही प्रभावी अर्थव्यवस्था में कई संरचना बनाई गई हैं जिनका समुचित उपयोग जलवायु अनुकूलन के निवेश को प्रभावी बना सकता है। पुरानी संरचनाओं और व्यवस्थाओं की उपादेयता और संभावनाओं का आकलन कर उचित योजना बनाने से सरंचनात्मक खर्चों को साधते हुए उपलब्ध संसाधनों को उपयोग अन्य प्रभावी उपायों को लागू करने में किया जा सकता है।

नई व्यवस्था के अनुकूल कौशल श्रमिक वर्ग में विकसित करने की भी आवश्यकता है। जीवाश्वम ईंधन के विकल्प के तौर पर क्लीन एनर्जी के विकल्प के रूप में सौर उर्जा, पवन उर्जा, जलविद्युत उर्जा आदि को भी देखा जा रहा है। इनके सफल संचालन के लिये स्थानीय समुदाय से युवाओं में कौशल प्रशिक्षण लाकर ही उर्जा रूपान्तरण को स्थायी किया जा सकता है। हालांकि इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोयला उद्योग की तुलना में गैर परम्परागत उर्जा उद्योग में मानव बल की काफी कम मात्रा में आवश्यकता होगी। अतः इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में संक्रमण के अनुसार उनसे संबंधित अन्य रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे और कौशल विकसित करना होगा।

खेती और पशुपालन व्यवस्था तथा वनोपज को समृद्ध और स्थायी खाद्य व्यवस्था अनुकूल बनाने के लिये प्राकृतिक तरीकों और देशज ज्ञान को प्रोत्साहित करना होगा। स्थानीय संसाधन आधारित कम लागत के टिकाऊ रोजगार और उद्यमिता के मॉडल भी विकसित करने की इनमें प्रचुर संभावना है। ■

जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण जीवन

– पूर्णिमा बिरुली

हमारे जीवन में जलवायु संकट का प्रभाव बहुत गहराई से पड़ रहा है। जब हम छोटे थे, उस समय वर्षा समय पर होती थी। समय पर वर्षा होने के कारण सही समय पर धान, दलहन और सब्ज़ियों की खेती की जाती थी। फल-फूल और कंदमूल अधिक मात्रा में उपजते थे। साथ ही खेतों में मछली, झींगा, केकड़ा आदि भी प्रचुर मात्रा में होते थे।

घर के आसपास और जंगलों में अनेक प्रकार के पशु-पक्षी और जीव दिखाई देते थे। कुओं में भरपूर पानी रहता था। चुवां, नदी और चापाकल से लोग पानी पीते थे। पीने के पानी की कोई कमी नहीं होती थी। गर्मी के मौसम में भी गाँव के लोग बिना पंखे के रह लेते थे। बरसात के दिनों में किसान खेती का काम करके शाम को घर लौटते थे, तो खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनता था। ठंड के समय सुबह-शाम आग तापी जाती थी। आम तौर पर गांव के घरों में पूरी रात लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़ों को आंगन में रखकर लगातार जलाया जाता था। घर के सदस्य रात में बीच-बीच में उठकर आग तापते और फिर सो जाते थे। इसी तरह हमारी रातें बीतती थीं।

जब से कल-कारखाने या कंपनियाँ शुरू हुई हैं, तब से हमारे खेत कंपनी से निकलने वाले धुएं और कचरे के कारण बंजर होते जा रहे हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण हो रहा है। खेतों में रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही है और खेतों को लाभ पहुँचाने वाले कीट तथा मछलियाँ समाप्त हो रही हैं। जंगलों की कटाई के कारण पशु-पक्षी भी नष्ट होते जा रहे हैं। वायु, मिट्टी और पानी के प्रदूषण के कारण साल भर असमय वर्षा हुई, जिससे खेतों में लगी फसलें नष्ट हो गईं। अधिक गर्मी के कारण भी फसलों को नुकसान पहुँचा है।

प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। घर के कामों से लेकर खेतों के काम, बच्चों का लालन-पालन और बुज़ुर्गों की देखभाल तक अधिकांश ज़िम्मेदारियां महिलाओं पर होती हैं, इसलिए महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ■

कोयले के दम पर प्रगति करेगा संताल परगना

संताल परगना की धरती के अंदर छिपा है 15.05 अरब टन कोयले का भंडार

संताल परगना की धरती आने वाले दशक में ऊर्जा, औद्योगिक निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। अनुमानित 15.05 अरब टन कोयले के भंडार और 28 चिह्नित कोल ब्लॉकों के साथ संताल परगना झारखंड और देश की ऊर्जा जरूरतों का मुख्य आधार बनने की क्षमता रखता है। दुमका, पाकुड़, गोड्डा और देवघर सहित कई जिलों में फैले ये ब्लॉक न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी नयी उम्मीदें जगा रहे हैं। संताल परगना में छिपे करीब 15.03 अरब टन कोयले की अनुमानित कीमत 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसका अनुमान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा कोयला मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट (2023-24) पर आधारित आंकड़ों से लगाया गया है। यह अकूत संपदा अगले 30-40 वर्षों में सरकार को रॉयल्टी, कर और अन्य शुल्कों से लगभग 40-60 हजार करोड़ का राजस्व प्रदान कर सकती है. क्षेत्र में दुमका जिले का योगदान सबसे बड़ा है, जहां 16 कोल ब्लॉकों में 6,441 मिलियन टन कोयला रिजर्व मौजूद है। पाकुड़ में पांच ब्लॉकों में लगभग 3,500 मिलियन टन कोयला है। गोड्डा और देवघर के ब्लॉकों को मिलाकर करीब 2,600 मिलियन टन का भंडार है।

थर्मल पावर प्लांट की जरूरतों को पूरा करेगा कोल ब्लॉक

मुख्य परियोजनाओं में दुमका के पचुवाड़ा साउथ और महुआगढ़ी, पाकुड़ के पचुवाड़ा नॉर्थ और सेंट्रल, देवघर का चितरा कोल प्रोजेक्ट और गोड्डा का राजमहल कोल प्रोजेक्ट शामिल है। ये ब्लॉक उच्च गुणवत्ता वाला सब-विटुमिनस कोयला थर्मल पावर प्लांट और बड़े उद्योगों को उपलब्ध करायेंगे। संताल परगना में कोयला उत्पादन से औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी, थर्मल पावर, स्टील और सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित होंगी, साथ ही मशीनरी निर्माण, मरम्मत, आपूर्ति, निर्माण सामग्री व सेवा उद्योग का विस्तार होगा, इससे स्थानीय व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे।

1.68 लाख लोगों के लिए स्थायी रोजगार की संभावना

कोयला उत्पादन से प्रत्यक्ष रोजगार के मौके भी सृजित होंगे। हर ब्लॉक में औसतन 1200 लोग खनन्, मशीनरी संचालन, सुरक्षा, तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में लगे होंगे, कुल 28 ब्लॉक मिलाकर प्रत्यक्ष रोजगार 33,600 लोगों को मिलेगा, इसके अलावा परिवहन, निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, मशीनरी सप्लाई और छोटे व्यवसायों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रत्येक प्रत्यक्ष रोजगार पर लगभग चार अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना होने से 1,34,400 अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होंगे। कुल मिलाकर संताल परगना में करीब 1.68 लाख लोगों के लिए स्थायी रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय व्यवसाय जैसे किराना, निर्माण सामग्री, वाहन सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार होगा. सड़कें, बिजली, जल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का विकास क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समृद्धि को मजबूत करेगा, पारंपरिक कृषि पर निर्भरता घटेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ेगी।

झारखंड का पाकुड़ जिला सिर्फ पत्थर खान और आदिवासी संस्कृति की पहचान तक सीमित नहीं है बल्कि यहां कोल माइनिंग (कोयला खनन) गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही है। जिस गति से यहां खदानों की पहचान उत्पादन और निवेश हो रहा है उसे देखकर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि आने वाले वर्षों में झारखंड की कैपिटल कही जाने वाला धनबाद को चुनौती देने की स्थिति में आ सकता है। पाकुड़ में सैकड़ों पत्थर की खदानें हैं और इस पत्थर की खासियत से पूरा देश अवगत है। वहीं कोयला ने नई पहचान दी है और आज पंजाब तथा बंगाल को रोशन करने में पाकुड़ जिला के कोयला का प्रमुख स्थान है। पाकुड़ जिले में कोयला का विशाल भंडार है जिसपर पूरे देश की नजर है।

– पर्यावरण संवाद डेस्क

जस्ट ट्रांजिशन से जस्ट ट्रांसफॉरमेशन की ओर

– घनश्याम

1970 का महत्वपूर्ण वर्ष! तब पश्चिमी और उत्तरी देशों में पर्यावरण का संकट एक गंभीर बहस का विषय बन कर उभरा! इसी बहस को आकार देने और उसे एक निर्णायक नतीजे तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के मजदूर संगठनों के दबाव के कारण एक नई अवधारणा को प्रतिपादित किया जिसका नाम दिया गया– 'जस्ट ट्रांजिशन'। यानी न्ययोचित बदलाव!!

तबसे लेकर अबतक यह यूरोप और अमेरिका में एक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इस अभियान के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आना पड़ा और 'कॉप' के नाम से एक पहल ने स्वरूप ग्रहण किया जिसका फूल फार्म है– 'कान्फ्रेन्स ऑफ द पार्टीज'। यह यू.ए.एफ.सी.सी.सी. का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसका काम है– जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक पहल को समन्वित करना और संकट के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतियां बनाना। इन्हीं रणनीतियों में एक रणनीति है– जस्ट ट्रांजिशन! यानी इसमें अवधारणागत दर्शन कम और सुधारात्मक रणनीतियां ज्यादा हैं।

यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि जलवायु संकट कोई आकाश से टपका हुआ कुप्रभाव नहीं है। बल्कि यह मुट्ठी भर मनुष्यों की बलवती विलासिता को येन-केन प्रकरेण पूरा करने की कवायद है। भले ही इसके लिये प्रकृति को विनष्ट करना पड़े, इंसान को गुलाम बनाना पड़े या फिर जल-थल-नभ तक प्रदूषण फैलाकर महामारी फैलाना पड़े। कोविड-19 इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है। कोविड 19 ने यह साबित कर दिया है कि अगर मनुष्य प्रकृति के सानिध्य में रहेगा तो महामारी भी उसे छू नहीं सकती। हमसबों ने देखा और पढ़ा है कि कोविड में जितने लोग मौत के शिकार हुए उनमें अधिकांश महानगरों के लोग थे। विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों को कोविड ने धर दबोचा और करोड़ों महानगरवासियों को यह चेतावनी दे डाली कि तुम्हारी सुविधाएं और सुरक्षा कवच महामारी के विषाणुओं को रोकने में सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ कोविड ने यह भी संदेश दिया कि जो प्रकृति के संरक्षण में रहेगा विषाणु उनतक फटक भी नहीं सकता। पूरी दुनिया के लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ आकाश और नदियों के निर्मल पानी ने यह साबित कर दिया कि जल और वायु के संकट का बड़ा कारण आधुनिक विकास से उत्सर्जित प्रदूषण है। इसलिये कोविड के बाद वैज्ञानिकों के समूह ने इस बात पर ज्यादा जोर देना प्रारंभ किया कि जस्ट ट्रांजिशन के बिना न तो जलवायु संकट से निजात पाया जा सकता है और न संभावित महामारी को रोका जा सकता है। ऐसा सोचना एक हद तो ठीक है लेकिन महज जस्ट ट्रांजिशन से जलवायु संकट का समाधान संभव नहीं है। जस्ट ट्रांजिशन की प्रक्रिया जलवायु संकट के समाधान का एक तकनीकी और तात्कालिक उपाय है। इसके लिए इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय पर गहन चिंतन करना होगा। वर्तमान समय में ऐसा संभव है कि जस्ट ट्रांजिशन की चिंतन धारा से शुरू कर वर्तमान संक्रमण कालीन अवस्था से तात्कालिक निजात पाया जाए लेकिन दीर्घकालिक समाधान के रास्ते भी ढूंढे जाएं। दीर्घकालिन समाधान

का रास्ता होगा जस्ट ट्रांसफॉरमेशन या टोटल ट्रांसफॉरमेशन विथ इक्वीलिटी एंड जस्टीस।

कुछ लोगों को यह दर्शन कपोल कल्पना लग सकता है लेकिन अगर समग्रता और व्यापकता में देखें तो यह बात बहुत साफ है कि जलवायु संकट व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रक्रिया से उपजे अतिकेन्द्रित चिंतन और तकनीक का दुष्परिणाम है। अतिरिक्त मुनाफा और गलाकाट प्रतिस्पर्धा का प्रतिफलन है।

इंसान को इंसान न समझकर उसे गुलाम बनाने के अमानवीय सोच और व्यवस्था की उपज है। प्रकृति पर विजय पाने का अंहकार और मुट्ठी भर लोगों को अजेय बनाने की महत्वकांक्षी कुत्सित चिंतन है।

ऐसे दिमागी फितुर से निकलकर सोचने का यह उपयुक्त समय है।

इसलिये कॉप-30 के दौरान दुनिया के अधिकांश देशों के प्रतिनिधियों ने ब्राजील के बेलेम में तमाम अंतर्विरोधों के बीच जो निर्णय लिया वह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसे बिंदुवार इस प्रकार देखा जा सकता है :-

- तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से एक समझौता किया जिसे जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म कहा गया। इसका उददेश्य है– स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय समुदायों और श्रमिकों को सहयोग करना है।
- उक्त समझौता से यह बात अब नीतिनिर्धारकों को समझ में आने लगी है कि महज सत्ता और पूंजी के वर्चस्ववादी चिंतन धारा से न्यायसंगत बदलाव संभव नहीं श्रमिकों को इसके केन्द्र में रखकर विशेष प्रयास और अभ्यास करना ही पड़ेगा। यानी सत्ता के नियंताओं और पूंजी के पुरोधाओं को आम जन और प्रभावित समुदायों के बीच जाना ही पड़ेगा और अपने अपराधों के लिये प्रायश्चित करना पड़ेगा।
- दूसरा महत्वपूर्ण समझौता यह हुआ कि सन् 2030 तक संपूर्ण दुनिया में प्राकृतिक वनों की कटाई पर रोक लगे और अमेजन के वनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। दुनिया के नीतिनिर्धारक यह अच्छी तरह जानते हैं कि अमेजन बेसिन के जंगल को अगर विनाश से नहीं बचाया गया तो जलवायु संकट का मामला और गहरा जायेगा।
- तीसरी महत्वपूर्ण सहमति यह हुई कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पूरे विश्व की मानवता को एकजुट करने का आहवान किया जाए। ब्राजील की भाषा में मुतिराओ यानी सामूहिक अभिक्रम की शब्दावली को वैश्विक स्वीकृति मिली।

लेकिन खेद की बात यह है कि ब्राजील की इस महती अधिकारिक जुटान में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने का कोई बाध्यकारी (बाइंडिग) समझौता नहीं हो पाया। इससे उन तमाम सम्पन्न देशों की मंशा स्पष्ट होती है कि वे सब जीवाश्म ईंधन के उत्खनन और उत्पादन से परहेज करने को अभी भी राजी नहीं है।

लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई इस शिखर सम्मेलन में महिलाओं, देशज लोगों और अफ्रीकी मूल के समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी गई और जलवायु शासन (क्लाइमेंट गोवरनेंस) में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इससे एक रास्ता खुलता हुआ नजर आता है कि जीवाश्म ऊर्जा और ईंधन के श्रोतों पर मनमानी और गैरकानूनी उत्खनन और उत्पादन पर रोक लगायी जा सकती है। इतना ही नहीं इन्हें बचाने के लिये चलाये जाने वाले संघर्षो के समर्थन में दुनिया का जनमत खड़ा हो सकता है।

तो बात महज जस्ट ट्रांजिशन तक की ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को "बसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा" को स्वीकार करते हुए 'जस्ट ट्रांसफॉरमेशन' की ओर जाने का संकल्प लेना होगा। उस दिशा में संतुलित कदम उठाते हुए ठोस पहलकदमी करनी होगी।

न्यायपूर्ण संक्रमणकालीन बदलाव से गुजरते हुए न्यायपूर्ण और समतामूलक बदलाव की दिशा की ओर बढ़ना ही होगा। प्रकृति और सृष्टि पर विजय के अहंकार से मुक्त होकर प्रकृति और सृष्टि से सानिध्य का रिश्ता कायम करना होगा। तभी संतुलित पर्यावरण और स्वच्छ जलवायु पूरी दुनिया को मिल सकेगा और एक खुशहाल माहौल बन सकेगा। ■

झारखंड का बदलता जलवायु

– डॉ. नितीश प्रियदर्शी

करोड़ों साल से झारखण्ड का जलवायु बदलता रहा है। काफी गर्मी पड़ी है, तो हिमयुग के भी अवशेष हैं। यहाँ 250 मिलियन वर्ष पहले भी घने जंगल थे। उस वक्त भी महाविनाश हुआ था पृथ्वी पर जिससे झारखण्ड भी अछूता नहीं था। उस युग में पृथ्वी पर से अधिकांश जीव नष्ट हो गए। वे जिस वजह से इसे 'महान मृत्यु' और पृथ्वी का सबसे घातक 'प्रजाति विलुप्ति' (Mass Extinctions) की घटना की संज्ञा दी जाती है। "जर्नल साइंस" में प्रकाशित शोध आलेख के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस प्रजातीय विलुप्ति के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। झारखण्ड में हिमयुग के अवशेष हजारीबाग के मांडू नदी से लेकर कोयला के बेसिन तक दिखते हैं। रामगढ़ से 20 किमी दूर मांडू के दूधी नदी वाले क्षेत्र में एक खास तरह का पत्थर पाया जाता है, जिसे गोलाश्म तल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन गोलाश्म तल से गोलाश्म की उत्पत्ति हिमनद से हुई है। यह करीब 300 मिलियन वर्ष पुराना साक्ष्य है। यह पत्थर जरवा गांव में दूधी नदी पर है। यह पत्थर हिमयुग का गवाह है और बताता है कि कभी इस क्षेत्र में भी ग्लेशियर हुआ करता था। दूधिनाला के आसपास बिखरे हुए ये पत्थर कई मायनों में अलग हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह धरती की उत्पत्ति के समय का ही है। सबसे आश्चर्यजनक यह है कि इस नदी में करीब एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी में ही हिम युग और समुद्र होने के अवशेष मिलते हैं। हिम के पिघलने व बहने के कारण चट्टानों में जो चिन्ह बनते हैं वे यहां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीवाश्म व पत्थरों के प्रकार भी यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसे में समझा जा रहा है कि हिम युग के बाद यहां कभी समुद्र हुआ करता होगा! हिमयुग में लाखों सालों तक झारखंड के पहाड़ों पर बर्फ पसरी हुई थी। जब ये बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो समुद्र तक का जलस्तर उठ गया था और यह झारखंड से डाल्टनगंज तक पहुंचा था। झारखंड में जुरासिक काल में भूगर्भीय हलचलों की वजह से ज्वालामुखी भी फटा था और उससे निकले लावे की मिट्टी को आज भी राजमहल में देखा जा सकता है। आज से 66 मिलियन वर्ष पूर्व झारखंड में काफी उथल-पुथल हो रहा था और यहां भूकंप की घटनाएं हो रही थीं। जब छोटानागपुर की पहाड़ियाँ उठ रही थीं और टूट रही थीं, उस समय यहां जल प्रपातों का निर्माण हो रहा था। यह वही समय था, जब भारत का प्लेट एशिया के प्लेट से टकराया था।

शोध की अगर माने तो विश्व में इस तरह के जंगल की आयु करीब 145 से 200 मिलियन वर्ष पुरानी है। रांची के आस पास के वनों में पेड़ों की आयु औसतन 50 से लेकर 500 वर्ष तक हो सकती है। लेकिन इस पर शोध की आवश्यकता है। लगभग एक मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर हिमयुग ने इस तरह के जंगल को ढक लिया। लेकिन आज से 12000 वर्ष पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ तो फिर से जंगल पनपने लगे। अगर रांची के आस पास के जंगलों की बात करें तो ये भी लाखों साल पुराने हो सकते हैं। सिर्फ पुराने पेड़ हटते गए और नए आते गए। पेड़ों का आकार बदलता गया तथा वन क्षेत्र कम होते गए। अगर झारखण्ड के साहेबगंज और राजमहल की बात करें तो वहाँ जो पेड़ों के अवशेष (फॉसिल्स) मिले हैं ये जुरासिक काल के हैं (जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज था), यानी 200 से 50 मिलियन वर्ष पहले के। झारखण्ड में 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले (Permian age) भी जंगल थे। लेकिन अब उनका सिर्फ फॉसिल्स के रूप में अवशेष दिखता है। पत्तों के रूप में। इन पत्तों के फॉसिल्स को आप यहाँ के दामोदर घाटी में कोयला खानों के पास शैल चट्टानों में देख सकते हैं। इन्ही जंगलों के चलते यहाँ हजारों साल से सभ्यता फलती-फूलती रही। इन्हीं जंगलों की वजह से रांची को उस वक्त बिहार का ग्रीष्म कालीन राजधानी घोषित किया गया। हम मनुष्य

आज अपने इस प्राचीन जंगल को खत्म करने में लगे हुए हैं। जंगल भी अस्वस्थ हो रहा है। जंगल है तो ऑक्सीजन है तथा पानी है वरना सब खत्म। प्रकृति का सबसे खूबसूरत नजारा झारखण्ड के जल, जंगल, जमीन में समाहित है, साथ ही झारखंड का सामाजिक ढांचा भी प्रकृति के अनुकूल ही है। झारखंडी मुख्यतः प्रकृति पूजक होते हैं। उनकी मूल पहचान ही प्रकृति से लगाव है। प्रकृति प्रेमी गुणों तथा व्यवहारों के कारण ही झारखंड आज तक गंभीर बीमारियों के चपेट से सुरक्षित रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में डेंगू, चिकनगुनिया, कालाज्वर, जापानी बुखार आदि जानलेवा बीमारियों की चपेट से बचा हुआ है।

झारखंडी अपनी सभ्यता और संस्कृति की बदौलत ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति से प्रगाढ़ प्रेम की वजह से ही झारखंडी अमन-पसंद तथा गंभीर स्वभाव के होते हैं. जिस तरह प्रकृति अपने ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना स्वयं चुपचाप कर लेती है, उसी प्रकार झारखंडी भी अपने ऊपर आने वाली विपत्ति का सामना चुपचाप कर लेता है। आदिकाल से अब तक विभिन्न प्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी झारखण्डी झारखण्ड क्षेत्र में अपनी पहचान, सभ्यता संस्कृति को बचाये रखा है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन पिछले 30 वर्षों से झारखण्ड का जलवायु बदल रहा है। कारण है औद्योगीकरण, खनिजों का उत्खनन, वाहनों का बढ़ना जिसके चलते वन क्षेत्र कम हुए, नदियां छोटी हो गई या सूखने लगीं, नदियां प्रदूषित होने लगी, पत्थरों के उत्खनन के फलस्वरूप पहाड़ गायब होने लगे, भूमिगत जल खत्म हो रहे हैं, गीली भूमि (वेट लैंड्स) का दायरा छोटा होने लगा है, वायु प्रदूषण पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। इन सब कारणों की वजह से झारखण्ड आज पहले की तुलना में गर्म हो रहा है। बारिश में भी कमी आई है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अल्पवृष्टि। बदलते जलवायु ने कृषि पर भी असर डाला है। बारिश के कम होने से अक्सर सूखा पड़ रहा है। राज्य के जलाशयों में घटता पानी बता रहा है कि बड़े शहरों में पीने के पानी की कमी हो सकती है। दूरदराज के गांवों में हालात ज्यादा खराब है। कुंओं का पानी तेजी से घट रहा है। सूखे का मतलब है कि छोटे किसानों का हाल और बुरा होगा। झारखण्ड के वन सम्पदा कम होने से भी यहाँ के बारिश पर भी असर पड़ा है। बारिश पहले की तुलना में कम हो रही है। जंगल और बारिश कम होने से यहाँ की नदियों पर भी असर पड़ रहा है। बहुत सी नदियां महीनों सूखी रहती हैं। ■

जलवायु परिवर्तन : गाँव की तबाही का कारण

– निरसो हांसदा

मैं जब छोटी थी उस समय गांव में साइकिल होती थी। हर एक घर में गाय, बकरी, सूअर पालन करते थे। टीवी मोबाइल भी नहीं थी। लोग डाक के द्वारा चिट्ठी भेजा करते थे। घर-घर बांस की चूर्ण और इमली पत्ते की चूर्ण रहती थी। खेतों में जैविक खाद का प्रयोग किया करते थे। देसी धान का ही उपयोग किया करते थे। खेत में कछुआ, केकड़ा, गोंडा, छोटी चिंगरी मछली खेत में मिलती थी। हर एक कच्चे घर के दीवाल में जो रंग लगता है वह भी मिट्टी का ही रंग लगता था। बच्चे घर के आस-पास कबड्डी, गोटी, लूका छिपी खेलते थे। लेकिन अब मनुष्य के जीवन में जलवायु परिवर्तन ने ऐसा कर दिया कि सभी लोग अपने घरों में जानवर को नहीं रख रहे हैं। खेत में अधिक धान होने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। उसके कारण खेत में रहने वाले केंचुवा और चिंगरी मछली भी नहीं मिल रही है। उन्नत चावल, साग सब्जी खाने के कारण हमारी आयु भी घटती जा रही है। साथ ही साथ हम बीमारी से जूझ रहे हैं। अब हर एक घर में बाईक और हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। गांव में बच्चे मोबाइल फोन के कारण दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना बंद कर रहे हैं। फिर जल नल योजना से जो नल का पानी है वह कुआँ और तालाब के पानी को सोख लेता है। नल चलाने से भी पानी नहीं निकलता है। आसपास के जंगल की कटाई के कारण जंगल के झरने भी सूख जा रहे हैं। साथी जानवर भी लुप्त हो रहे हैं। अब किसान अकाल के समय से ठेका मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। जिसके कारण खेती में कमी हो रही है। उसके कारण बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। जो गांव में बचे हुए किसान है वे भी सब अब तकनीकी रूप से ट्रैक्टर से हल चलवा रहे हैं। मशीन से कटाई की जा रही है। अब कहीं भी आप रास्ते से जाते हैं तो धूल इतनी उड़ती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह पर्यावरण परिवर्तन अपने यहां तेजी से बदलता दिख रहा है। ■

सुन्दरपहाड़ी में आयोजित वन्य खाद्य मेला

– कृष्ण कान्त

गोड्डा जिले के सुन्दरपहाड़ी में हाल ही में 24 नवम्बर 2025 को आयोजित वन्य खाद्य मेला वहां की आदिवासी और विशेषकर सौरिया पहाड़िया समुदाय की परम्परागत खाद्य व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये महत्वपूर्ण प्रयास था जिसे राईजअप लीडरशिप के अन्तर्गत अभिव्यक्ति फाउण्डेशन द्वारा कॉमन ग्राउण्ड, सारथी - जस्ट ट्रान्जिशन नेटवर्क, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय के सम्मिलित प्रयास से आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय मेला का उद्देश्य राजमहल क्षेत्र के पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली वन्य खाद्य विविधता के प्रदर्शन से लोगों को जागरूक और इनके संरक्षण सम्वर्द्धन के लिये सचेष्ट करना था। यह मेला इस क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर जन चेतना और परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिये एक अभिनव प्रयास था और इसके अन्तर्गत पहली बार लोग अपने क्षेत्र की विशाल खाद्य व्यवस्था को एक ही जगह पर जमा होकर अपनी विरासत और इसके संरक्षण पर चर्चा कर रहे थे।

आदिवासी समाज खासकर आदिम जनजातियों के लिये जंगल उनकी जीविका, जीवनशैली और संस्कृति का अभिन्न अंग है और इनके बिना आदिवासी जीवन की कल्पना भी असंभव है। समुदाय आदि पूर्वजों के काल से ये जंगल ही समुदाय के भोजन, जलावन, औषधि, पशु चारा सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते आ रहे हैं और इस कारण से समुदाय अपनी पहल से जंगलों की रक्षा भी करता आया है। वन्य नियम और कानून आने के बाद से समुदाय का वनों पर अधिकार कम होता गया और इस भागीदारी की आवश्यकता को महसूस करते हुए संयुक्त वन प्रबंधन और कई प्रकार के पहल लगातार होते आये हैं।

मेला आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अभिव्यक्ति फाउण्डेशन के सचिव कृष्ण कान्त ने बताया कि राईजअप लीडरशिप के अन्तर्गत संस्था के द्वारा पहाड़िया समुदाय के साथ गोड्डा और पाकुड़ जिले में वन्य परम्परागत खाद्य व्यवस्था का एक अध्ययन किया गया था जिसमें खाद्य विविधता की गिरती स्थिति और इससे समाज विशेषकर महिलाओं पर बढ़ते दुष्प्रभाव का आकलन किया गया था। उन्होंने बताया कि आज से पांच दशक पहले तक समुदाय जंगल, नदियों और परम्परागत स्रोतों से अपनी दैनिक भोजन की आवश्यकता का पचहत्तर प्रतिशत पूर्ति करता था वहीं आज यह घट कर पच्चीस प्रतिशत पर सिमट गया है। आज भी हमारे जंगल, नदियों और सामूहिक क्षेत्रों में 42 किस्म की साग सब्जियां, 34 प्रकार के फल, 14 तरह के कन्द मूल, 5 तरह के शहद, 10 प्रकार के मशरूम

सहित प्रचुर मात्रा में मछली, घोंघा और अन्य जीव उपलब्ध हैं जो कि समुदाय के लिये निशुल्क और उच्च पोषण युक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्य स्रोत रहे हैं। वर्तमान में मुद्रा विनिमय और बाजार पर निर्भरता से इनका उपयोग व उपलब्धता घटती जा रही है, वहीं भोजन की विविधता में कमी का बुरा असर महिलाओं और बच्चों में बढ़ते कुपोषण के रूप में दिख रहा है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा तथा राज्य में जलवायु परिवर्तन के नोडल पदाधिकारी श्री रवि रंजन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या के तौर पर बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर वनों की घटती विविधता के रूप में दिख रही है। इसके उपाय के लिये वन विभाग और समुदाय सहित सभी वर्गों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने मेला में अभिव्यक्ति फाउण्डेशन, बदलाव फाउण्डेशन और प्रदान द्वारा लगाये गये स्टॉल में पहाड़िया समुदाय द्वारा प्रदर्शित जंगल से प्राप्त भोजन की विविधता को देखते हुए हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अगले वर्ष से इस मेले के नियमित आयोजन में वन विभाग पहल करेगा।

गोड्डा के प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी श्री वाघ पवन शालिग्राम ने इस खाद्य विविधता और परम्परागत ज्ञान की सराहना करते हुए कहा कि इस विविधता के कारण ही वन्य क्षेत्र में जीवन है वह शहर और बड़े बाजारों में भी उपलब्ध नहीं है। इसको निरन्तर और अक्षुण्ण रखते हुए इसका मूल्य संम्वर्धन करने की जरूरत है जिससे जीविका के नये अवसर के साथ भोजन और पोषण तंत्र को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाया जा सके।

सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड प्रमुख प्रमिला टुडू ने मेला में पहाड़िया समाज द्वारा प्रदर्शित खाद्य पदार्थ और व्यंजनों की प्रदशर्नी की सराहना करते हुए कहा कि आज अधिकांश लोग विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी भोजन की आदतों में बदलाव आने के कारण इस विविधता से अनजान होते जा रहे है और इसलिये भी उनकी भागीदारी में कमी आती जा रही है जिससे भोजन के लिये अन्य व्यवस्थाओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अपनी जैव विविधता के बल पर स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर खाद्य व्यवस्था को मजबूत करना आदिवासी समाज का अहम कर्तव्य है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी है।

बड़ा सिन्दरी के मुखिया राम पहाड़िया ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी आज की पीढ़ी पहले जैसी मजबूत नहीं है और दिनोदिन कमजोर होती जा रही है। परम्परागत खाद्य को अपना कर एक स्वस्थ जीवनशैली और खाद्य स्वावलम्बन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

इस मौके पर उपलब्ध आदिवासी समुदाय की महिलाओं ने एक स्वर से कहा कि हमारे जंगल की विविधता बढ़ाने के लिये नये वनरोपण के काम में कम से 20 प्रतिशत तक परम्परागत खाद्य प्रजातियों को शामिल करने से ही इस विविधता को अक्षुण्ण रखा जा सकेगा और उपस्थित सभी लोगों ने इसपर समवेत सहमति भी जताई। वन विभाग ने भी इस अवसर पर उपयुक्त प्रजातियों की नर्सरी बनाने पर सहमति दिखाई और इसके लिये सभी की सहभागिता का आह्वान किया। ■

जलवायु संकट का मेरा अनुभव

– सालगे मार्डी

जलवायु परिवर्तन और जलवायु संकट से सम्बंधित मेरे जीवन के छोटे-छोटे अनुभव कुछ इस प्रकार हैं - पृथ्वी का मौसम और पर्यावरण की स्थिति इतनी खराब और असंतुलित हो गई है कि इसने जलवायु संकट का रूप ले लिया है। पहले मौसम आने के समय का पता होता था। गर्मी कब आएगी और सर्दी, बरसात कब? इसका पता होता था। किसान खेती करने के लिए रोहण नक्षत्र से ही धान बुआई शुरू कर देता था। धान की रोपाई जुलाई के अंत तक हो जाती थी। अब तो मौसम का मिजाज कुछ समझ में आता ही नहीं है। कभी भीषण गर्मी से सूखे का प्रभाव, कभी भीषण बारिश से बाढ़ का आना और घर द्वार टूट जाना अब आम बात है। भीषण आंधी और ठनका से भी जानमाल की क्षति हो रही है।

जलवायु संकट के प्रभाव को छोटे-छोटे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब मैं छोटी थी उस समय सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी और शाम भी चिड़ियों की चहचहाहट से ढलती थी। अपने घर के बाड़ी में भिन्न-भिन्न प्रकार की चिड़िया जिसमें सबसे ज्यादा मैना पक्षी होती थी। अब मैंना, गौरैया, कौवा देखने को भी नहीं मिल रहे हैं।

बरसात में धान के खेतों में विभिन्न मछलियां, घोंघी, कछुआ केकड़ा आदि हुआ करते थे। इन दिनों केकड़ा, घोंघी, तुड़, मांगुर, चिंगड़ी नहीं के बराबर है। केकड़ा खेतों में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा धान खेती के बाद उगाये जाने वाले चना, तीसी, मसूर, अरहर की खेती प्रचुर मात्रा में हुआ करती थी। अभी मौसम बिगड़ने के कारण अरहर, चना में दाना नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण किसान निराश हो रहे हैं। लगभग किसानों ने दलहन खेती छोड़ दी है। उसके बाद खेतों में पाए जाने वाले साग भी नहीं उग पा रहे हैं। हर घर की बाड़ी में विभिन्न फसल मकई, भिन्डी, घंघरा तथा विभिन्न प्रकार के साग हुआ करते थे जो कि शरीर के लिए लाभकारी हुआ करते थे। अनियमित बारिश और मौसम के उतार चढ़ाव ने इन फसलों को खत्म कर दिया है।

इन परिस्थितियों को लाने में कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का सबसे बड़ा हाथ है। मनुष्य तथाकथित विकास की अंधीदौड़ में तेजी से भागना चाहता है। मनुष्य मेहनत करने से कतरा रहा है। उन सुख सुविधाओं और विकास के परिणामों को जाने बिना हम मनुष्य अंधाधुंध भागे जा रहे हैं।

हम अगर खेती से लेकर उद्योग तक में अभी की स्थिति देखें तो पाते हैं कि मनुष्य मुनाफा की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। किस तरह की खेती करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। औद्योगिक विकास का उद्देश्य तो मुनाफा कमाना ही है। पर खेती को भी लोग मुनाफा का केंद्र बना दिया है। रासायनिक खाद दवा का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जिससे हमारे सहयोगी जीव जंतु हमारे बीच से लुप्त हो रहे हैं।

जलवायु संकट की बात हर कोई कर रहे हैं पर समाधान की पहल नहीं के बराबर है। अनावश्यक वस्तुओं की भरमार हर घर में देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति की मार गांव के लोगों को झेलनी पड़ रही है। जिन जंगलों को गांव के लोग बचाते आ रहे हैं, उन जंगलों में सरकार भी छोटे-बड़े उद्योग लगाने की परमिशन दे रही है। अभी तक मेरे बचपन में पूर्वी सिंहभूम में जितनी हरियाली थी धीरे-धीरे कम हो रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में ही नहीं बल्कि अविभाजित सिंहभूम में छोटे-बड़े हजारों कारखाने लगाये गए हैं। शहरों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। इसका बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। साथ में बाकी जनजीवन, जीव, जंतु, पेड़-पौधों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ■

जस्ट ट्रांजिशन यात्रा : जलवायु संकट से निजात पाने की एक पहल

– गुलाब चंद्र

आज पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही हैI जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इससे चिंतित होकर कॉप में शामिल देशों ने 2015 में पेरिस समझौता किया। इस समझौते में पूरी धरती के तापमान डेढ़ डिग्री कम करने की योजना पर सहमति बनी, और इसे 2030 और 2070 तक तापमान को 2 डिग्री कम करने की योजना पर पूरी दुनिया ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तापमान बढ़ने के मूल कारण अधिक जीवाश्म ईंधन जलाने को माना गया है। इसी जीवाश्म ईंधन को बिना जलाए ऊर्जा प्राप्त करने की एक टाइम लाइन तय की गई जिसे जीवाश्म एनर्जी लेस टाइम लाइन कहा गया। जीवाश्म ईंधन को जलाए बिना ऊर्जा को प्राप्त करना भविष्य का लक्ष्य हो गया है। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष रूप से ध्यान देने की योजना बनी और इस पर काम शुरू हो गया। लेकिन भारत में 73% ऊर्जा जीवाश्म इंधनों से ही प्राप्त होती है। जिसमें थर्मल पावर मुख्य है। अगर भारत में जीवाश्म ईंधन को जलाए बिना ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो एक बड़े क्षेत्र में कोयला पर निर्भर लोगों की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? झारखण्ड में ऊर्जा का मुख्य साधन जीवाश्म ईंधन को जलाकर थर्मल पावर के माध्यम से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

इस अवस्था में झारखंड में अगर ऊर्जा रेनेवल एनर्जी से प्राप्त की जायेगी तो झारखंड में कोयला पर निर्भर लाखों लोगों के रोजगार के साधन क्या होंगे? झारखंड में कोयला खनन उद्योग तथा थर्मल पावर झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर झारखंड में कोयले के खनन और थर्मल पावर बंद हो जाते हैं तो इन उद्योगों पर निर्भर हितधारक या हजारों प्रत्यक्ष एवं लाखों अप्रत्यक्ष लोगों का रोजगार का क्या होगा? इन समुदायों की आर्थिक गतिविधियों को कैसे बनाए रखा जायेगा? स्थानीय जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो सकेगी? एक समावेशी विकास एवं टिकाऊ विकास को आगे कैसे ले जाएगें- इसकी चिंता करने की जरूरत है। इन्हीं जरूरत को आधार बनाकर सारथी नामक नेटवर्क ने झारखंड में जस्ट ट्रांजीशन यात्रा 2025 का आयोजन 5 नवंबर से 12 नवंबर तक की. सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह से लेकर बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उली हातु तक 13 जिलों से होते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए 8000 लोगों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया। कोयलांचल क्षेत्र के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग के शहरी इलाकों में अबुआ भागीदारी– अबुआ भविष्य जस्ट ट्रांजिशन यात्रा के उद्देश्यों को केंद्र में रखकर यात्रा की गई।

झारखंड भारत का वह राज्य है जहाँ धरती की गोद में अपार खनिज संपदा, सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और विविधता से भरपूर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। यह भूमि न केवल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है, बल्कि जल-जंगल-ज़मीन पर आधारित जीवन, आदिवासी समुदायों की परंपराओं और सामुदायिक मूल्यों के कारण भी विशिष्ट पहचान रखती है। लेकिन पिछले कई दशकों में कोयला आधारित अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भरता ने राज्य की सामाजिक संरचना, पर्यावरणीय संतुलन और आजीविका के पारंपरिक आधारों पर गहरा प्रभाव डाला है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण, भूमि क्षरण, जल

स्रोतों के सूखने, जैव-विविधता के कम होने, विस्थापन, बेरोज़गारी और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकट लगातार गहराते गए। इसने समुदायों के जीवन को अस्थिर किया है और विकास की असमानता को बढ़ाया है। ऐसे परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन एक और बड़ा वैश्विक खतरा बनकर उभरा है। अनियमित मानसून, लंबे सूखे, अत्यधिक तापमान, अचानक होने वाली आपदाएँ, कृषि पर बढ़ता दबाव और आजीविका की अनिश्चितता- ये सभी संकेत बताते हैं कि झारखंड को अब एक नई दिशा और नई सोच की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि राज्य को अब ऐसी विकास यात्रा अपनानी होगी जिसमें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक अवसरों का सृजन और सामाजिक न्याय- तीनों समान रूप से संतुलित हों। इन्हीं उभरती जरूरतों, बदलते समय की मांग और जनभागीदारी की भावना को केंद्र में रखकर "अबुआ भागीदारी – अबुआ भविष्य : जस्ट ट्रांजिशन यात्रा" की परिकल्पना की गई। यह यात्रा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य को सुरक्षित, समावेशी और सतत बनाने की सामूहिक पहल है।

यह यात्रा झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं को नमन करती है। यह उन महापुरुषों को याद करती है जिन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव, बीर बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, बुधु भगत और असंख्य नायक जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। जस्ट ट्रांज़िशन यात्रा उक्त संघर्ष की आधुनिक गूंज है, जिसमें विकास समानता, साझेदारी और पर्यावरणीय संतुलन से जुड़ा है। जस्ट ट्रांज़िशन यात्रा झारखंड की विकास यात्रा की एक नई दिशा देने का प्रयास है। ऐसी दिशा जिसमें खनन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर हरित और सतत विकल्प तलाशे जाएँ। ऐसी जिसमें आदिवासी ज्ञान और प्रकृति आधारित परंपराएं विज्ञान और आधुनिकता से मिलकर नई संभावनाएं पैदा की जा सके। ऐसी दशा जिसमें नीति और समाज के बीच की दूरी कम हो और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर आवाज को स्थान मिले। हमारा सपना है एक ऐसा झारखंड जहां विकास न्याय पूर्ण हो। जहां कोई समुदाय हाशिए पर न रहे। जहां जंगल और नदियां अविरल बहे और जहां हर व्यक्ति की भागीदारी से न्यायपूर्ण भविष्य गढ़ा जाए!

सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क, झारखंड में सामाजिक काम कर रहे 30 संस्थाओं का समूह है। सारथी नेटवर्क ने झारखंड में जस्ट ट्रांजीशन के भविष्य के समस्याओं के समाधान के लिए कई बैठकों के बाद झारखंड में अबुआ भागीदारी–अबुआ भविष्य जस्ट ट्रांजीशन यात्रा जन सहयोग से करने का निर्णय लिया। झारखंड के सभी जिले के साथी 4 नवंबर को ही भोगनाडीह पहुंच गए और यात्रा 5 नवंबर को सिद्धू कान्हु के जन्म स्थल से शुरू की गई। सभी जिलों से आए हुए प्रतिभागियों ने सिद्धू कान्हू के जन्म स्थल पर नारे लगाए– सिद्धू-कान्हू, बिरसा वीर... हूल जोहार, हूल जोहार! जल, जमीन हमारा है, इसे बचाना है। जीवन बचाना है। सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव, फूलो, झानो, मकी, देवमनी को माला अर्पण करने के बाद सिद्धू कान्हू के सातवें वंशज मनोज मुर्मू का यात्रा की ओर से सम्मान किया गया। सभी यात्रियों ने सिद्धू कान्हू के सपनों के झारखंड बनाने का आह्वान किया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संवर्धन करते हुए सामुदायिक चेतना और अपनी संस्कृति परंपराओं को संरक्षित करने कि बात कही गई। झारखंड की समृद्धि के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा सिद्धू कान्हू के घर जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाद में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संवाद के वरिष्ठ समाजसेवी पर्यावरणविद् घनश्याम ने कहा कि विकास में सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है। विकास तभी संभव है जब हमारे प्राकृतिक धरोहर सामुदायिक हाथों

में रहेगा। उन्होंने कहा जस्ट ट्रांजीशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा बदलने मात्र की नहीं है बल्कि भविष्य की चेतना को जागृत करने की है। जब हम जस्ट ट्रांजीशन की बात करते हैं तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बात कर रहे हैं। इसलिए सिद्धू कान्हू ने कहा था कि यहां के नौजवान आगे नहीं आएंगे तो जल, जंगल, जमीन नहीं बचेंगे। यहां की संस्कृति नहीं बचेगी। आज से 170 वर्ष पहले सिद्धू कान्हू ने न्याय संगत बदलाव की बात कही थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उन्होंने कहा था कि रेल लाइन बिछाने से हमारे जंगल और नदियां बर्बाद हो जाएगी हमारे पहाड़ बर्बाद हो जाएंगे। और आज हम फिर कह रहे हैं कि जंगल, जमीन, पहाड़, नदी बचाओ।

यह संदेश सिद्धू कान्हू पहले ही दे चुके थे। इसलिए आज के समय में आज के विकास में आंख मूंद कर के विकास करना यानी हमारी नदियां, पहाड़, जंगल और संस्कृति बर्बाद करना है। और यही है हमारा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन संकट का रूप ले लेगा तो समाज संकट में होगा। आज यही हो रहा है। आज हजारों लोग बीमार हैं। झारखंड में आज आधी आबादी कुपोषित हैं। और जब इन बातों को कहते हैं तब हमें विकास विरोधी कहा जाता है। हम विकास चाहते हैं लेकिन हम वैसा विकास चाहते हैं जिसमें हमारा जंगल बचा रहे। हमारी नदियां बची रहे, हमारे पहाड़ बचे रहे, हमारी संस्कृति बची रहे। लेकिन हम विनाश की बुनियाद पर विकास नहीं चाहते। हम न्याय संगत विकास चाहते हैं। जिससे प्रकृति बची रहे और हमारी पीढ़ी कुपोषित नहीं रहें। बेरोजगार नहीं रहें। महिला, बच्चे खुशहाल रहे। और इसीलिए यह यात्रा है। यह यात्रा कोयला खदान या कोयले से निर्माण ऊर्जा को खत्म करने के लिए नहीं है। बल्कि कोयला खदान के बदले वैकल्पिक ऊर्जा की तलाश करनी है। हमारी वैकल्पिक ऊर्जा क्या होगी? हमारी ऊर्जा बदलाव में प्रकृति का विनाश नहीं होगा। प्रदूषण नहीं फैलेगा। हम वैसी ही ऊर्जा की तलाश में हैं जो प्रकृति के संरक्षण करते हुए विकास को बढ़ाएगा। इसलिए यह यात्रा सिद्धू कान्हू की धरती से बिरसा की धरती उलिहातू तक होगी। इस यात्रा से हम विकास की अवधारणा को समझेंगे। झारखंड की अपनी संस्कृति और परंपरा क्या-क्या है, इसको समझेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी में हमारी आजीविका और हमारी प्राकृतिक धरोहर संरक्षित रहे। हम ऐसा ही विकास चाहते हैं। जब हम ऊर्जा परिवर्तन की बात करते हैं तो आने वाले ऊर्जा में हमारे सारे प्राकृतिक संसाधन और हमारी परंपरा संस्कृति सभी संरक्षित रहे। हम वैसे ही विकास की कल्पना के साथ यह यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम ऐसी ऊर्जा का कल्पना करते हैं जिससे आदमी बचा रहे। हमारी प्राकृतिक धरोहर बची रहे और हमारे आने वाले भविष्य की आजीविका को संरक्षित करते हुए न्याय पूर्ण विकास हो। सबका सम्मान हो। सबके लिए विकास हो। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। आने वाले समय में हम झारखंड में एक ऐसे न्यायपूर्ण बदलाव की कल्पना करते हैं जिसमें समुदाय केंद्र में रहे। यात्रा में सांस्कृतिक टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं गीत के माध्यम भोगनाडीह

से संदेश देने का प्रयास किया गया। हमें प्रकृति के साथ विकास करना है और अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा करनी है। जस्ट ट्रांजीशन का अर्थ समझाते हुए नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने एक ऐसे विकास की कल्पना प्रस्तुत की जिसमें सबका विकास और न्याय पूर्ण विकास हो।

उलिहातू खूंटी में यात्रा का समापन

12 नवम्बर सुबह 7:00 बजे उलिहातू के लिए यात्रा प्रस्थान किया। उलिहातू पहुंचने के क्रम में उलिहातू के रोड में ग्रामीण बसाहट की व्यवस्था दिखाई दी। उनके पास खलिहान करने के लिए समतल भूमि का अभाव है इसलिए सड़कों पर ही ज्यादातर धान की झड़ाई हो रही थी। झारखंड अलग राज्य हुए 25 साल हो गए हैं लेकिन आज भी झारखंड के लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़कें जरूर बन गई है लेकिन ग्रामीणों के जीवन में बहुत बदलाव नहीं आया है। उनकी मूलभूत सुविधाएं आज भी जंगल और खेत पर ही निर्भर हैं। उनकी परंपरागत हुनर को विकसित कर आजीविका के नए साधन खड़े किये जा सकते हैं– ऐसा महसूस हुआ उलिहातू पहुंचकर। पहली बार यह महसूस किया कि अंग्रेजों और महाजनों से बिरसा मुंडा ने किस तरह से अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। उलिहातू एक पवित्र स्थल है जहां बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। यात्रा उसी उलिहातू गाँव में जाकर समाप्त हुई।

इस समापन समारोह में बिरसा मुंडा के वंशज मुख्य अतिथि थे। उनकी उपस्थिति ने यात्रा की समाप्ति की सार्थकता को बढ़ा दिया था। ढोल, नगाड़े और पाइका नृत्य से संस्कृति और परंपरा का संदेश दिया गया कि आज भी प्रकृति के साथ रहने वाले लोग अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। अभाव में रहते हुए भी वे अपने प्राकृतिक मूल्यों को आत्मा से लगाए हुए हैं। यह भविष्य के विकास को मूल्य आधारित बनाने का अनमोल सिद्धांत है।

समापन समारोह में झारखंड के 22 जिलों के साथी शामिल हुए। समापन समारोह में बिरसा मुंडा के जन्म स्थल में परंपरागत रूप से बिरसा मुंडा के वंशज के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद सभी यात्रियों को नमन करने के लिए जन्म स्थल पर स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण करने दिया गया। सभी यात्री बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सभा में शामिल हुए। जहां पर बिरसा मुंडा के वंशजों को स्मृति चिन्ह, गमछा, टी-शर्ट, टोपी के साथ स्वागत किया गया। ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा सभी यात्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद समापन समारोह में झारखंड के दर्शन को रखते हुए तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए फ़िया फाउंडेशन के डायरेक्टर जॉनसन जी ने स्वागत भाषण किया और कहा कि ऊर्जा, कृषि, रोजगार और लैंगिक समानता सभी कुछ जलवायु संकट से प्रभावित होने वाले हैं। इस पर बातें करनी जरूरी है। उन्होंने जलवायु संकट से उबरने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त होने की जरूरत पर बल दिया।

समापन समारोह के मौके पर संवाद के घनश्याम जी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें विकास का मूल्यांकन करना होगा।

अगर आज का विकास हमारे प्राकृतिक धरोहर को नष्ट करने के लिए है तो ऐसे विकास के प्रति सोचने की जरूरत है। हम वैसा विकास चाहते हैं जिसमें हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारी जमीन और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। हम ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें कुपोषण और लैंगिक असमानता न हो।

इस समापन समारोह में साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पाकुड़, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ के साथी शामिल हुए तथा एक आह्वान किया गया कि जलवायु संकट से निपटने में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। सारथी नेटवर्क जस्ट ट्रांजीशन (न्यायपूर्ण बदलाव) को जमीनी स्तर से ऊपर तक पहुंचाने का काम करेगा। इस आह्वान के साथ मुन्ना झा एवं फ़िया फाउंडेशन के ऋचा जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया और यात्रा के समापन की घोषणा की। ■

महिला नेतृत्व कार्यशाला का नवाँ चरण

जलवायु संकट का महिलाओं पर प्रभाव

'संवाद' द्वारा दिनांक 3-5 दिसंबर 2025 को महिला नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन एस.डी.सी., रांची में किया गया। इस कार्यशाला का विषय - 'जलवायु संकट का महिलाओं पर प्रभाव' रखा गया। कार्यशाला में कुल 37 प्रतिभागी शामिल हुए जिसमें 22 महिला, 15 पुरुष थे।

कार्यशाला की शुरूआत एक गीत "सोहान लागे रे" से हुई। सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. नीतिश प्रियदर्शी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की बात गांवों से शुरू होनी चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव गांवों में ज्यादा पड़ा रहा है। कृषि, आजीविका सहित उनके पूरे जीवन को यह प्रभावित करता है।

जबसे धरती बनी है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पहले यह बदलाव धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से होता था पर अब तेजी से और कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित कारणों से हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठंड कम पड़ रही है। वर्षा भी अनियमित हो रही है।

ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यह किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी के औसत तापमान में लंबे समय तक होने वाली वृद्धि है जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधि जैसे जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) जलाने एवं वनों की कटाई से हो रही है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन जैसे गैस ज्यादा मात्रा में वातावरण में आ जाते हैं। CO_2 को पेड़ ग्रहण करता है। पेड़ों का रसोईघर पत्ता है। पेड़ वातावरण से CO_2 लेकर अपना भोजन बनाता है। CO_2 की आयु 120 वर्ष और मिथेन की आयु भी 20 वर्ष है। अगर पेड़ CO_2 ग्रहण नहीं करें तो इसकी भयावहता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र में बदलाव आता है और हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं।

अनियमित बारिश, पानी की कमी हमारे कृषि को प्रभावित करती है। फसल कम होती है। आजीविका की पूर्ति के लिए लोग पलायन करते हैं। हमारे शरीर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लोग कई तरह की बीमारियों जैसे बैचेनी, अनिंद्रा, चिड़चिड़ापन के शिकार होते हैं।

जलवायु संकट का सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। पुरूष जब आजीविका की तलाश में पलायन करते हैं तो महिलाओं पर तिहरा बोझ पड़ता है। खेती-किसानी, घर के कामों के साथ-साथ उन्हें बाहर मजदूरी भी करनी पड़ती है। पानी की उपलब्धता कम होने से उन्हें बहुत दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। पानी की कमी से वे मासिक धर्म के समय सफाई एवं स्वच्छता का ख्याल ठीक से नहीं रख पाती है। एक अध्ययन के अनुसार बिहार के कुछ गांवों में माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया है। यह भूमिगत जल प्रदूषित होने के कारण हुआ होगा।

अतः हमें प्रकृति को समझना होगा। उसे सम्मान देना होगा। पहले की जो जीवन शैली थी उसे याद कर अपनाना होगा। प्रकृति हमें बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए जो चीज जहाँ है उसे वहीं रहने दो उसे मत छेड़ो। छोटी-छोटी चीजों में बदलाव लाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं।

दूसरे सत्र को आगे बढ़ाते हुए संजय बसु मल्लिक ने कहा कि जलवायु संकट को जानने के पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जलवायु क्या है?

जल और वायु, इन दोनों में वैसा ही रिश्ता है जैसे मछली पानी के अंदर जिन्दा है ठीक उसी प्रकार इंसान भी हवा के कारण जिन्दा है।

हवा में तीन उपादान है - नाइट्रोजन, कार्बनडाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वायुमंडल में यह कितनी मात्रा में रहेगा। यह हम तय नहीं करते हैं यह पृथ्वी तय करती है। वायुमंडल और मानव के रिश्ते में सामंजस्य है। सामंजस्य गड़बड़ाने से

जीवन में असर पड़ता है। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है पर इसकी अधिकता भी नुकसानदेह है। ऑक्सीजन ज्यादा होने से भी लोग मरते हैं। कोविड के समय ज्यादातर लोग ऑक्सीजन की अधिकता से मरे। कारण ज्यादा ऑक्सीजन उनके फेफड़ों को जला दिया।

यह दुनिया कार्बन से बनी है। हम भी कार्बन से बने हैं और हमारे शरीर के अंदर आग है। कार्बन के साथ जब दूसरा उपादान जुड़ता है तब उसका रंग बदलता है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो ईंधन, आक्सिजन और उष्मा के सम्मिलन से जलती है। तो संकट कहाँ है? अर्थात जो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक हो नहीं रहा है वह संकट है। अगर हम किसी को जरूरत से ज्यादा कंबल ओढ़ाते जाते हैं तो एक समय बाद उसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी वह अपने को स्वाभाविक महसूस नहीं करेगा। उसी तरह धरती को अगर जरूरत से ज्यादा कार्बनडाइऑक्साइड की चादर ओढ़ाते जायें तो संकट पैदा होता है। पेड़ और समुद्र कार्बन को खींचते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता है। धरती सोचती है सूरज का किरण रात को नहीं मिलेगा इसलिए इसे पकड़र रखो। जलवायु को मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों ने बिगाड़ा है। खासकर जीवाश्म ईंधन (कोयला, गैस, तेल) के जलने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है और मौसम भी बदल रहा है।

इसके बाद के सत्र में छंदोश्री ने अपनी बात रखते हुए लाह की खेती पर जलवायु संकट का क्या-क्या कुप्रभाव पड़ रहा है इस पर सहभागियों का ध्यान खींचा।

सम्पा राय ने जलवायु संकट और महिला पर उसके प्रभाव पर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि हम पहले के तापमान और अभी के तापमान में अंतर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वायुमंडल में व्याप्त कुछ गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि सूर्य की गर्मी को सोखकर पृथ्वी को गर्म करती है। जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई आदि से CO_2 जैसे गैस की मात्रा बढ़ती है और धरती गर्म होने लगती है। पेड़ पौधे वायुमंडल में व्याप्त CO_2 को सोखते हैं जिससे उसकी मात्रा बढ़ नहीं पाती है पर पेड़ कटने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। पशुओं के मल से भी मिथेन गैस निकलती है जिससे भी पृथ्वी गर्म होती है। जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदायें बाढ़, सूखा, आंधी तूफान बढ़े हैं।

इसके बाद सभी प्रतिभागियों को 4 समूह में बांटा गया और जलवायु परिवर्तन का महिलाओं को क्या-क्या समस्या हो रही है और इसका समाधान क्या है?

इस पर ग्रुप में चर्चा हुई। यह चर्चा काफी महत्वपूर्ण थी और इससे प्रतिभागियों को बहुत कुछ सीखने को मिला।

– पर्यावरण संवाद डेस्क

खेती-किसानी महज व्यवसाय नहीं, बल्कि सामुदायिक संस्कृति

भारत जैसे देश में खेती-किसानी महज एक व्यवसाय/रोजगार नहीं है बल्कि यह एक संस्कृति है। इसीलिए तो गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने यहां की खेती, किसानी और पानी तथा उससे जुड़ी जीविका और जीवन को अरण्य संस्कृति कह कर संबोधित किया था।

झारखंड, बिहार, ओड़िशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे भू-जैविक भू-भाग के लिए यह संबोधन शत प्रतिशत सही है। लेकिन आज यह संस्कृति खतरे में है। तमाम प्राकृतिक धरोहर संकट में हैं। खेती-किसानी और पानी न सिर्फ प्रदूषित हो रहे हैं बल्कि जहरीले बनाये जा रहे हैं। सदासलिला नदियों पर कारपोरेट्स कब्जा जमाने को उतावले हैं। तमाम कॉमन लैंड (सामुदायिक जमीन) पर कारपोरेट्स की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। जंगल को कारपोरेट्स के हाथों में सौंपने की तैयारियां चल रही हैं।

अगर ऐसा हुआ तो सारी खेती, किसानी चौपट हो जायेगी। खेतों से किसान बेदखल कर दिये जायेंगे। जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली जायेगी।

नदियां प्रदूषित कर दी जायेंगी। करोड़ों मछुआरों की जिंदगी तबाह हो जायेगी। खेती और नदियों पर आधारित आजीविका के सभी स्रोत बर्बाद हो जायेंगे। करोड़ों किसान आत्महत्या की तरफ धकेल दिए जायेंगे।

उक्त तमाम भयावह परिस्थितियों के खिलाफ एक संगठित अभियान चलाने के लिए 'खेती-किसानी बचाओ मंच' का गठन किया गया है। यह एक मुहिम है जिसके वाहक किसान और मजदूर होंगे। इसमें युवा हिरावल दस्ते का काम करेगा। प्रशिक्षित युवा और युवतियों का जत्था वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ायेगा।

यह अभियान मानता है आज खेती, किसानी भयंकर संकट के दौर से गुजर रही है। आजादी के बाद खेती-किसानी और किसान के लिए सबसे बुरा दौर सामने आया। और यह हुआ इसलिए है कि 90 के दशक में अपने देश के शासकों ने डंकल प्रपोजल से उपजे वैश्विक संगठन 'विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) पर हस्ताक्षर कर देश की आजादी गिरवी रख दी। डब्ल्यू टी ओ के बनाए कानून ने उन तमाम देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया जो अब तक खेती, किसानी और हवा-पानी के मामले में स्वतंत्र थे। और, उन देशों ने अपना कानून धड़ाधड़ बदलना शुरू किया। अपनी नीति और नियम थोपने शुरू किए। इस पूरी प्रक्रिया को मजबूत किया आवारा पूंजीवाद ने। इसके वाहक बने सभी देशों के कारपोरेट्स। इन कारपोरेट्स और संबंधित देशों की शासकों की मिलीभगत ने उन तमाम देशों की प्राकृतिक धरोहरों पर कब्जा करना शुरू किया। खेती-किसानी उन्हीं धरोहरों में से एक है।

– पर्यावरण संवाद डेस्क

जस्ट ट्रांजिशन : वैश्विक विमर्श, जलवायु संकट और कलाकार की संवेदनात्मक पहल

आज विश्व एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बन गया है। जलवायु परिवर्तन, खनन और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला पर्यावरणीय विनाश सबसे अधिक आदिवासी, श्रमिक और स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर रहा है। इसी संदर्भ में "जस्ट ट्रांजिशन" यानी न्यायपूर्ण परिवर्तन की अवधारणा उभरी है। यह केवल जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर जाने की यात्रा तक ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि बदलाव का बोझ कमजोर वर्गों पर न पड़े। इसका उद्देश्य आजीविका की सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के संरक्षण को साथ लेकर चलना है।

दुनिया के कई देशों में जस्ट ट्रांजिशन पर नीतिगत बहसें चल रही हैं। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अनेक हिस्सों में यह समझ बन रही है कि जलवायु संकट का समाधान केवल तकनीक से संभव नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक हस्तक्षेप और रचनात्मक अभिव्यक्तियों की भी आवश्यकता है।

इसी संदर्भ में झारखंड की कलाकार पुनीता कुमारी का कलात्मक अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आयी है। पुनीता बताती हैं कि जस्ट ट्रांजिशन की थीम पर सोहराई पेंटिंग बनाने का अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। पुनीता कुमारी ने सोहराई पेंटिंग के माध्यम से झारखंड के जंगल-जमीन, प्रकृति और आदिवासी ज्ञान परंपरा के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में खनन से हुए विनाश और अब संभावित बदलाव के दौर को चित्रित किया है।

मिट्टी के लाल, पीले, काले और सफेद रंगों से बने चित्रों में प्रयुक्त प्रतीकों के रूप में जंगल, पशु-पक्षी, नदी, खेत और मानव आकृतियाँ एक ओर खनन से पहले के संतुलित जीवन को दर्शाती हैं, तो दूसरी ओर खदान, टूटी बिखरी धरती और बदलता सामाजिक परिदृश्य संकट और असंतुलन के संकेत देते है। चित्रों के बॉर्डर में प्रयुक्त पारंपरिक ज्यामितीय और प्राकृतिक पैटर्न समुदाय की निरंतरता और सांस्कृतिक स्मृति को रेखांकित करते हैं।

पुनीता की पेंटिंग्स जस्ट ट्रांजिशन को एक दृश्य कथा में बदल देती हैं, जहाँ कला जलवायु संकट और सामाजिक बदलाव के बीच सेतु का काम करती है। ऐसी संवेदनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्तियाँ ही जस्ट ट्रांजिशन को केवल नीतियों और योजनाओं की सीमाओं से बाहर निकालकर जन-सरोकारों से जोड़ेंगी और उसे जमीनी हकीकत से जोड़कर, संवेदनशील तथा बदलाव की दिशा में सार्थक पहल में मदद करेंगी।

– शेखर

पाइका नृत्य की तस्वीरें